क्रांति समय
हिन्दी दैनिक अखबार में विज्ञापन, प्रैस नोट, जन्म दिन की शुभकामनाएँ, या अपने विस्तार में किसी भी समस्या को अखबार में प्रकाशित करने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 9879141480

दैनिक
क्रांति समय

RNI.No. : GUJHIN/2018/75100

क्रांति समय
हमारे यहां पर एल.आई.सी., कार-बाईक-ट्रक का इन्सयोरेंशन, रेल टिकट, एयर टिकट बनवाने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 8980974047

संपादक : सुरेश मौर्या मो. 9879141480
E-mail: krantisamay@gmail.com
सूरत, वर्ष: 02 अंक: 130, बुधवार, 05 जून, 2019, पेज: 4, मुल्य 1 रु.
रजीस्ट्रड ऑफिस:- 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात
Email: krantisamay@gmail.com Web site : www.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

प्रसार भारती की स्वायत्तता महत्वपूर्ण है, हम इसे बरकरार रखेंगे : जावड़ेकर

नई दिल्ली। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि केंद्र की नई सरकार प्रसार भारती की स्वायत्तता को बरकरार रखेगी। जावड़ेकर ने यहां दूरदर्शन भवन में अत्याधुनिक हाई डेफिनेशन डीएसएनजी वैनों का लोकार्पण किए जाने के अवसर पर सोमवार को कहा, ''प्रसार भारती की स्वायत्तता महत्वपूर्ण है। हम इसे बरकरार रखेंगे।... हम चाहते हैं कि प्रसार भारती सुचारू तरीके से काम करे, नए कार्यक्रम लेकर आए और नए आयाम छुए।'' मंत्री ने विश्वसनीय कार्यक्रमों और कवरेज के लिए सार्वजनिक प्रसारकों डीडी और आकाशवाणी की प्रशंसा की और अधिकारियों से डी डी भारती जैसे चैनलों को प्रोत्साहन देने को कहा। उन्होंने कहा कि नई वैनों के माध्यम से डीडी को आउटडोर स्थलों से अच्छी गुणवत्ता के विजुअल एकत्र करने में मदद मिलेगी। डीडी न्यूज ने 17 हाई डेफिनेशन डीएसएनजी वैन खरीदी हैं जो एचडी और मल्टी कैमरा प्रोडक्शन में संकेत प्रसारित करने में सक्षम हैं। प्रसार भारती के अध्यक्ष सूर्यप्रकाश ने कहा कि सार्वजनिक प्रसारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ''सबका विश्वास'' नीति की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सूचना एवं प्रसारण सचिव अमित खरे ने कहा कि सरकार ने 1,054 करोड़ रुपए के खर्च पर प्रसार भारती के बुनियादी ढांचे में विकास के लिए तीन वर्षीय एक योजना को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा, ''हमारे देश में कई चैनल सबसे तेज होने का दावा करते हैं लेकिन डीडी और आकाशवाणी सर्वाधिक विश्वसनीय हैं।'' उन्होंने कहा कि डीडी और आकाशवाणी के देश में सर्वाधिक दर्शक एवं श्रोता हैं।

इसी सप्ताह मिल जायेगा भाजपा को नया कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष

अब पार्टी सूत्रों की मानें तो भाजपा को एक सप्ताह के भीतर ही नया कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है भाजपा में जल्द ही संगठन के चुनाव होने हैं ऐसे में पूर्णकालिक पार्टी अध्यक्ष संगठन चुनावों के बाद ही बनेगा

नई दिल्ली।

भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री बन चुके हैं और पार्टी के एक व्यक्ति एक पद सिद्धांत के चलते उन्हें एक पद छोड़ना होगा। जाहिर सी बात है अमित शाह भाजपा अध्यक्ष पद उसी तरह छोड़ने जा रहे हैं जैसे 2014 में राजनाथ सिंह ने केंद्र सरकार में गृहमंत्री बनने के बाद भाजपा अध्यक्ष का पद छोड़ दिया था। अब पार्टी सूत्रों की मानें तो भाजपा को एक सप्ताह के भीतर ही नया कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है। भाजपा में जल्द ही संगठन के चुनाव होने हैं ऐसे में पूर्णकालिक पार्टी अध्यक्ष संगठन चुनावों के बाद ही बनेगा। सितंबर 2018 में हुई भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर संगठन चुनावों को लोकसभा चुनाव तक टाल दिया गया था। भाजपा के संविधान के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव संगठन चुनावों के संपन्न होने या फिर पचास फीसदी से राज्यों में संगठन के चुनाव पूरे होने के बाद ही हो सकता है। इस वर्ष अक्तूबर में हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव होने हैं इसलिए संभावना है कि तब तक शायद पचास फीसदी से ज्यादा राज्यों में भाजपा के संगठन चुनाव संपन्न नहीं हो पायें इसलिए कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति की जा सकती है। कार्यकारी अध्यक्ष पद के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के अलावा भाजपा महासचिव भूपेंद्र यादव का नाम भी शामिल है। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय भी रेस में बने हुए हैं। नड्डा के प्रभाव वाले उत्तर प्रदेश, यादव के प्रभार वाले बिहार तथा गुजरात और विजयवर्गीय के प्रभार वाले पश्चिम बंगाल में भाजपा का लोकसभा चुनावों में शानदार प्रदर्शन रहा है। हालांकि नड्डा का नाम सबसे आगे इसलिए है क्योंकि वह पार्टी महासचिव के तौर पर राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और अमित शाह के साथ काम कर चुके हैं और फिलहाल भाजपा की निर्णायक इकाई संसदीय बोर्ड के सचिव भी हैं। भाजपा सूत्रों ने यह भी बताया कि लोकसभा चुनावों में जोरदार जीत के बाद अब पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक संसद सत्र के बाद जुलाई या अगस्त में बुलाई जा सकती है। इस बैठक को भव्य रूप देने की तैयारियां शुरू हो गयी हैं। संभावना जताई जा रही है कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक भाजपा इस बार पश्चिम बंगाल में करेगी जहाँ लोकसभा चुनावों में उसने 18 सीटें जीतकर जबरदस्त प्रदर्शन किया है।

कांग्रेस ने किरकिरी के बाद जोड़ा सीताराम केसरी का नाम

नई दिल्ली।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और स्वतंत्रता सेनानी सीताराम केसरी का नाम अपनी वेबसाइट से हटाने को लेकर हुई किरकिरी को कांग्रेस ने सुधार लिया है। पार्टी ने अब अपनी वेबसाइट पर पूर्व अध्यक्षों की सूची में सीताराम केसरी का नाम डाल दिया है। लेकिन इस बार कांग्रेस ने एक और गलती कर दी है। पार्टी ने अपनी साइट पर से सोनिया गांधी का नाम ही हटा दिया है। 1990 से 2018 के बीच कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षों की सूची में अब केवल तीन नाम ही दिख रहे हैं। इन तीन नामों में पहला नाम पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव का है। इसके बाद सीताराम केसरी का नाम है और अंत में राहुल गांधी का नाम दिया गया है। जबकि थोड़ी देर पहले इसी सूची में दो बार सोनिया गांधी का नाम दिया गया था लेकिन सीताराम केसरी का नाम नहीं था।

बता दें कि मंगलवार सुबह ही खबर आई थी कि कांग्रेस के अध्यक्ष रहे नेताओं की लिस्ट में से दिवंगत अध्यक्ष सीताराम केसरी का नाम नहीं है। सीताराम केसरी बिहार के पिछड़े वर्ग से आते थे। केसरी साल 1996 से 1998 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। लेकिन पार्टी वेबसाइट में पूर्व अध्यक्षों की लिस्ट में उनका नाम नहीं है। हालांकि अब पार्टी ने उसे सही कर लिया है। पार्टी ने बयान जारी कर कहा कि सीताराम केसरी का नाम किसी तकनीकी खराबी की चलते छूट गया। अब ठीक कर लिया गया है। बता दें कि राजीव गांधी के निधन के बाद पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। सितम्बर 1996 में नरसिंह द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद सीताराम केसरी के हाथ में कांग्रेस की कमान सौंपी गई थी। केसरी मार्च 1998 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। केसरी के बाद पार्टी की कमान सोनिया गांधी ने संभाली थी।

इस तरह हुई केसरी की विदाई: बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, '9 मार्च 1998 को केसरी ने इस्तीफे की घोषणा कर दी, लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद उन्होंने अपना मन बदल लिया। केसरी ने दावा किया कि उन्होंने तो इस्तीफ़े के बारे में सिर्फ़ मंशा ज़ाहिर की थी। हालांकि सभी प्रमुख अखबारों ने उनके हवाले से छापा था कि केसरी ने इस्तीफा दे दिया है। सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई, केसरी ने बैठक के मिनिट्स पर आपत्ति जताई।

सचिन पायलट मेरे बेटे वैभव की हार की जिम्मेदारी लेंः अशोक गहलोत

नई दिल्ली।

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच चल रही खींचतान अब सबके सामने आ गयी है। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक टीवी समाचार चैनल से बातचीत में कहा है कि उनके बेटे वैभव गहलोत की हार की जिम्मेदारी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट को लेनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि जोधपुर मुख्यमंत्री गहलोत के प्रभाव वाला क्षेत्र है जहाँ से उनके बेटे वैभव गहलोत को भाजपा उम्मीदवार गजेंद्र सिंह शेखावत ने चार लाख मतों से ज्यादा के अंतर से चुनाव हरा दिया। राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों पर भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को जीत मिली है। मुख्यमंत्री गहलोत के इस बयान पर उपमुख्यमंत्री पायलट ने आश्चर्य जताया है लेकिन कोई टिप्पणी करने से इंकार कर दिया है। टीवी चैनल को दिये साक्षात्कार में जब गहलोत से पूछा गया कि क्या पायलट ने जोधपुर से उनके बेटे को उम्मीदवार बनाने का सुझाव दिया था तो गहलोत ने कहा, अगर उन्होंने ऐसा किया तो यह अच्छा है और दर्शाता है कि हमारे बीच कोई मतभेद नहीं हैं। साथ ही उन्होंने कहा, 'पायलट साहब ने उस समय कहा था कि जोधपुर संसदीय सीट में कांग्रेस के छह विधायक हैं और हमारा चुनाव प्रचार भी अच्छा चल रहा है इसलिए वैभव गहलोत को बड़ी जीत हासिल होगी। इसलिए मुझे लगता है कि जोधपुर में कांग्रेस की हार की जिम्मेदारी सचिन पायलट को लेनी चाहिए।' मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि इस बात का ठीक से समीक्षा होनी चाहिए कि क्यों हम इस सीट पर इतनी बुरी तरह हार गये। गहलोत का सचिन पायलट पर यह पलटवार तब सामने आया है जब लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद से पायलट समर्थक मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं कि उनकी कार्यशैली की वजह से ही कांग्रेस की सभी सीटों पर हार हुई जबकि मात्र छह महीने पहले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए अपनी सरकार बनाई थी।

लोकसभा स्पीकर की रेस में मेनका गांधी और राधामोहन सिंह का नाम सबसे आगे

आठ बार सांसद बन चुकी मेनका गांधी भाजपा की सबसे अनुभवी लोकसभा सदस्य हैं

नई दिल्ली।

लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए भाजपा का शीर्ष नेतृत्व उम्मीदवारों के नाम पर मंथन कर रहा है तथा पूर्व केन्द्रीय मंत्री मेनका गांधी, राधामोहन सिंह एवं वीरेन्द्र कुमार सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को इस पद की दौड़ में शामिल माना जा रहा है। सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संभावित उम्मीदवारों में पूर्व केन्द्रीय मंत्री जुएल ओराम एवं एस एस अहलुवालिया के भी नाम शामिल हैं। आठ बार सांसद बन चुकी मेनका गांधी भाजपा की सबसे अनुभवी लोकसभा सदस्य हैं और वह अध्यक्ष पद के लिए एक

स्वाभाविक विकल्प हैं। सत्रहवीं लोकसभा में सबसे अनुभवी सांसद होने के कारण उन्हें कार्यवाहक अध्यक्ष चुना जा सकता है। राधामोहन सिंह भी छह बार सांसद का चुनाव जीत चुके हैं और उन्हें भी अध्यक्ष पद के लिए एक मजबूत दावेदार माना जा रहा है। सिंह की संगठन पर गहरी पकड़ है तथा उनकी छवि विनम्र एवं सबको साथ लेकर चलने वाले नेता की है। सूत्रों ने कहा कि वीरेन्द्र कुमार भी छह बार से सांसद हैं और उनकी दलित छवि उनके पक्ष में काम कर सकती है। अहलुवालिया पिछली सरकार में संसदीय कार्य राज्य मंत्री थे और विधायी मामलों में उनकी जानकारी के कारण वह विख्यात हैं। भाजपा नेताओं के एक वर्ग का मानना है कि पार्टी नेतृत्व दक्षिण भारत से किसी नेता का चयन कर सबको हैरत में डाल सकता है। सूत्रों ने बताया कि लोकसभा उपाध्यक्ष का पद बीजू जनता दल (बीजद) को इस बार दिया जा सकता है तथा कटक से सांसद भृर्तुहरि महताब का नाम इस पद के लिए विचार किया जा रहा है। महताब को 2017 में सर्वोत्तम सांसद के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सोलहवीं लोकसभा में उपाध्यक्ष पद पर अन्नाद्रमुक के एम थम्बी दुरै को आसीन किया गया था। सत्रहवीं लोकसभा की पहली बैठक 17 जून को होगी। अध्यक्ष पद के लिए 19 जून को चुनाव होगा। निचले सदन में भाजपा नीत राजग के पास करीब दो तिहाई बहुमत होने के कारण लोकसभा अध्यक्ष पद इसी के पास जाना तय है।

एएन-32 की खोज जारी, एक दिन बाद भी नहीं मिला कोई सुराग

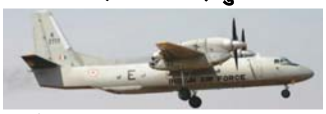

नई दिल्ली। असम के जोरहाट से उड़ान भरने के बाद भारतीय वायुसेना का एएन-32 विमान सोमवार को लापता हो गया था। लापता हुए विमान एएन-32 में चालक दल के आठ सदस्य और पांच यात्री सवार थे। वायुसेना ने एएन-32 विमान का पता लगाने के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों को काम पर लगाया है जिसमें सुखोई-30 और सी-130 शामिल है पर अब तक विमान का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। सेना के सी -130 जे और जमीनी गश्ती दल अभी भी तलाशी अभियान चला रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि उन्होंने इस बारे में वायुसेना के उपप्रमुख से बात की है और वे इन यात्रियों के सुरक्षित रहने की कामना करते हैं। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, ''कुछ समय से लापता वायु सेना के एएन-32 विमान के संबंध में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल राकेश सिंह भदौरिया से बातचीत की। उन्होंने मुझे वायुसेना के इस लापता विमान को लेकर उठाये गए कदमों की जानकारी दी। मैं इसमें सवार सभी यात्रियों की सुरक्षा के लिये प्रार्थना करता हूं।''

बुआ ने भतीजे से कहा, पहले खुद को साबित करो तभी करेंगे गठबंधन

नई दिल्ली।

बसपा अध्यक्ष मायावती ने लोकसभा चुनाव के परिणाम की समीक्षा के बाद आज प्रेस वार्ता में कहा कि अखिलेश यादव और उनकी पत्नी ने मेरा काफी सम्मान किया और मैं भी इस रिश्ते को निभाने के लिए तैयार हूं। राजनीतिक मजबूरियों की बात करते हुए मायावती ने कहा कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनावों में उनकी पार्टी अकेले लड़ेगी। उन्होंने कहा कि सपा में जब तक सुधार नहीं हो जाता तब तक सपा के साथ चलना बसपा के लिए मुश्किल है। हालांकि उन्होंने कहा कि गठबंधन पर फिलहाल परमानेंट ब्रेक नहीं लगा है। पूर्व सीएम ने कहा कि अखिलेश पहले खुद को साबित करें फिर गठबंधन की बात करें। मायावती ने कहा कि हमें हार से काफी निराशा हुई है और इस हार में श्वङ्करू ने भी अपनी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि हमने भाजपा को हटाने के लिए हमने गठबंधन किया था पर हमारे गठबंधन का कोई फायदा नहीं हुआ। इसके अलावा

मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में अभी बड़े बदलाव की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यादव बहुल इलाके में भी सपा का वोट हमें ट्रांसफर नहीं हुआ। सपा अपने गढ़ में खुद चुनाव हार गई। आपको बता दें कि दिल्ली स्थित बसपा कार्यालय में बैठक में पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष आर एस कुशवाहा, राज्य में पार्टी के सभी विधायक, नवनिर्वाचित सांसद, प्रदेश के सभी जोनल कोऑर्डिनेटर के अलावा सभी जिला अध्यक्षों को भी बुलाया गया था।

भीषण गर्मी से जूझ रहा भारत, चूरू में सबसे ज्यादा 50.3 डिग्री सेल्सियस पर पारा

नई दिल्ली। भारत के कई हिस्सों में इस सप्ताह भी लू से राहत नहीं मिली।देश में सबसे ज्यादा तापमान राजस्थान के चूरू जिले में दर्ज किया गया। चूरू में तापमान 50 डिग्री से ल्सियस के स्तर को पार कर गया। भारतीय मौसम विभाग ने यह जानकारी दी। दिल्ली में तापमान में थोड़ी गिरावट रही। पालम ऑब्जर्वेटरी ने को अधिकतम तापमान 42.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। पारा 42.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया था। दिल्ली में मंगलवार को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने गरज, आसमान में बादल छाए रहने तथा बिजली कड़कने की संभावना है जिससे भीषण गर्मी से मामूली राहत मिलने के आसार हैं। राजस्थान का चूरू लगातार तीसरे दिन देश में सबसे ज्यादा गर्म रहा। यहां अधिकतम तापमान 50.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके बाद दूसरे स्थान पर श्रीगंगानगर (48.8डिग्री) रहा। बीकानेर में 48.4 डिग्री और कोटा में 47.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से चार डिग्री सेल्सियस से आठ डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि आगामी 48 घंटे में पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान प्रचंड लूकी चपेट में रहेंगे। वहीं, हरियाणा में लू की स्थिति बनी रही। यहां हरियाणा में नारनौल में सबसे ज्यादा तापमान 47.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह तापमान सामान्य से पांच डिग्री ज्यादा है। हिसार में अधिकतम तापमान 45डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। यह सामान्य से तीन डिग्री ऊपर है। वहीं, पंजाब के अमृतसर में तापमान सामान्य से दो डिग्री अधिक 42.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जब कि लुधियाना में अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, दोनों राज्य में कई जगहों पर अगले कुछ दिनों में लू से राहत मिल सकती है।

कर्नाटक में सियासी संकट, जेडीएस प्रदेश अध्यक्ष ने अपने पद से दिया इस्तीफा

बंगलूरू। लोकसभा चुनाव 2019 में नरेंद्र मोदी की सुनामी से सभी क्षेत्रीय क्षत्रपों के राजनीतिक भविष्य पर ग्रहण सा लग गया है। जिसका असर राज्य दर राज्य देखने को मिल रहा है। दक्षिण के राज्य कर्नाटक में सत्ता पर काबिज कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन के बीच खींचतान की खबर तो आम बात है। लेकिन लोकसभा चुनाव में भीषण पराजय के बाद राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी जेडीएस की आपसी कलह भी देखने को मिल रही है। जेडीएम के प्रदेश अध्यक्ष एच विश?वनाथ ने अपने पद से इस?तीफा दे दिया है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में राज?य की 28 लोकसभा सीटों में से भाजपा ने 25 सीटों पर जीत दर्ज की थी जबकि कांग्रेस और जेडीएस को एक-एक सीटों पर जीत हासिल हुई थी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन की करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस के नेताओं में भी असंतोष देखने को मिला था। कांग्रेस नेता रामलिंगा रेड्डी ने अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य के नेताओं और केंद्रीय स्तर के नेताओं के बीच समन्वय की कमी के चलते हार का सामना करना पड़ा।

ममता ने EVM पर उठाये सवाल- लोकतंत्र बचाने के लिए बैलेट पेपर से हों चुनाव

उन्होंने कहा, ''मैं लोकसभा चुनाव के नतीजों को जनादेश के तौर पर स्वीकार नहीं करती हूं

कोलकाता।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के इस्तेमाल को लेकर सोमवार को सवाल उठाये और विपक्षी दलों से अपील करते हुये कहा कि वे मतपत्रों के जरिए चुनाव करवाने की मांग संयुक्त रूप से करें। बनर्जी ने कहा कि एक तथ्यान्वेषी समिति बननी चाहिये ताकि वह

हाल में हुए चुनावों में इस्तेमाल ईवीएम का ब्योरा तैयार कर सके। उन्होंने पार्टी के विधायकों और राज्य के मंत्रियों से चुनावों में तृणमूल कांग्रेस की पराजय को लेकर हुई बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, ''हमें लोकतंत्र बचाना है। हम मशीन नहीं चाहते, हमारी मांग है कि कागज के मतपत्र वाले युग की वापसी हो। हम एक आंदोलन प्रारंभ करेंगे और यह बंगाल से शुरू होगा।'' उन्होंने कहा, ''मैं सभी 23 विपक्षी राजनीतिक दलों से कहूंगी कि वे साथ आयें और मतपत्रों की वापसी की मांग करें। अमेरिका जैसे देश में भी ईवीएम पर प्रतिबंध लगा हुआ है।'' बनर्जी ने कहा कि तथ्यान्वेषी समिति इस बात का पता लगाएगी कि क्या मशीनें प्रोग्राम्ड थीं या नहीं। उन्होंने कहा, ''मैं लोकसभा चुनाव के नतीजों को जनादेश के तौर पर स्वीकार नहीं करती हूं।'' बनर्जी ने कहा, ''मैं सभी विपक्षी दलों से अपील करती हूं कि वे एक तथ्यान्वेषी समिति का गठन सुनिश्चित करें, ताकि हम इस तरह के चुनाव नतीजों के ठीक-ठीक वजह का पता लगा सकें।'' तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने आरोप लगाया कि भाजपा ने चुनाव जीतने के लिए धन, बाहुबल, संस्थाओं, मीडिया और सरकार का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा, 42 लोकसभा सीटों वाले इस राज्य में वाम मोर्चे के कारण 18 सीटें जीतने में सफल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा,''भाजपा का दावा था कि वे 23 सीटें जीतेंगे पर, वे 18 ही जीत सके..और वह भी वामदलों की वजह से। लेकिन हम (तृणकां) अपना वोट शेयर चार फीसदी बढ़ाने में सफल रहे।

संपादकीय

केजरीवाल का दांव

दिल्ली मेट्रो और डीटीसी की बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा देने की घोषणा करके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अगले विधानसभा चुनाव के लिए एक बड़ा दांव चला है। गौरतलब है कि अगले साल की शुरुआत में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, और राजधानी में महिला कामगारों की तादाद अच्छी-खासी है। हालांकि इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए उन्हें अभी दो-तीन महीने तक इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन यह तय है कि वोटिंग से पहले वह कई महीने तक इस सुविधा का लाभ उठा चुकी होंगी। मुख्यमंत्री ने महिला सुरक्षा का हवाला देते हुए इस कदम को जायज ठहराया है। इसमें तो कोई दोराय नहीं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मेट्रो सबसे सुरक्षित और आरामदेह सार्वजनिक सुविधा है, मगर पिछले दिनों बढ़े किराये के बाद बहुत सारे लोगों के कदम जेब के दबाव में इसकी तरफ बढ़ने से ठिठकने लगे थे। बावजूद इसके दिल्ली सरकार का यह कदम लोक-कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की ओट में एक लोक-लुभावन पहल ही है।अभी-अभी संपन्न लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को भारी शिकस्त झेलनी पड़ी है। राज्य की सात लोकसभा सीटों में से पांच में उसके प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहे। ऐसे में, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अपने पुराने नुस्खे को फिर से आजमाया है। पिछले विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने दिल्ली के हरेक परिवार को प्रतिमाह 20 हजार लीटर पानी मुफ्त में मुहैया कराने और बिजली का बिल आधा करने का यकीन दिलाया था और सत्ता में आने के चंद घंटों के भीतर उन्होंने अपने इन दोनों वादों को पूरा भी किया। इसलिए भी उनका ताजा फैसला उनके राजनीतिक विरोधियों को बेचैन करेगा। स्कूली शिक्षा व सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी दिल्ली सरकार के प्रयासों ने कुछ बेहतर मुकाम हासिल किए हैं। सार्वजनिक परिवहन वह बड़ा क्षेत्र था, जिसमें आम आदमी की रोजाना की दुश्वारियां बाकी हैं। दिल्ली के लोग जाम और वायु प्रदूषण की चपेट में किस कदर फंसे हैं, इसकी गवाही एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसले देते हैं। इस लिहाज से भी सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने के किसी फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन क्या सार्वजनिक संसाधन किसी को बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध कराए जाने चाहिए? तब, जब सरकारें आर्थिक रूप से आरामदेह स्थिति में न हों। यह प्रवृत्ति राजनीतिक लाभ से प्रेरित तो है ही, सांस्थानिक विफलता को भी ढकती है, और इसे किसी एक पार्टी या सरकार तक महदूद नहीं रखा जा सकता। अर्थव्यवस्था और राज्य की माली हालत को ताक पर रखकर लगभग सभी पार्टियों व सरकारों ने गहने, लैपटॉप, टीवी, स्मार्टफोन से लेकर चावल, दूध, घी तक बांटा है या बांटने का वादा किया है। किसानों की समस्याओं को भी हल करने में ईमानदारी बरतने की बजाय सरकारें इसी तरह के लोक-लुभावन कदमों के जरिए उन्हें बहलाती रही हैं। ऐसी नीतियों पर अब गंभीरता से गौर करने की जरूरत है। अपने राज्य की स्त्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हरेक सरकार का अहम दायित्व है, लेकिन उनकी मुकम्मल सुरक्षा मेट्रो या बस में मुफ्त यात्रा की सुविधा में नहीं, बल्कि अन्य उपायों के साथ टिकट खरीदकर उसमें सफर करने की आर्थिक हैसियत हासिल करने में है। दुर्योग से सरकारें इस पर ज्यादा नहीं सोचतीं।

विकास के नजरिये से देखें वित्तीय घाटा

भरत झुनझुनवाला

निवर्तमान एनडीए सरकार के वित्तमंत्री अरुण जेटली द्वारा वित्तीय घाटे पर नियंत्रण करने की नीति को लागू किया गया था। उनके कार्यकाल के दौरान वित्तीय घाटे में कमी भी आई है लेकिन इस सार्थक कदम के बावजूद देश की आर्थिक विकास दर 7 फीसदी के करीब सपाट रही है। नये वित्त मंत्री के सामने चुनौती है कि जेटली की इस नीति पर पुनर्विचार करें। वित्तीय घाटे के मूलमंत्र को समझना होगा। वित्तीय घाटे का अर्थ होता है कि सरकार के खर्च अधिक और आय कम है। आय से अधिक किये गए खर्च के लिए रकम जुटाने के लिए सरकार ऋण लेती है। सरकार को ऋण देने के लिए रिज़र्व बैंक नोट छापता है। नोट छापने से महंगाई बढ़ती है और अर्थव्यवस्था में अस्थिरता पैदा होती है। इसलिए वित्तीय घाटे को नियंत्रित करने की सीख दी जाती है। मान्यता है कि वित्तीय घाटा नियंत्रण में रहेगा तो महंगाई भी नियंत्रण में रहेगी। जैसा पिछले पांच वर्षों में हमने देखा है। महंगाई के नियंत्रण में रहने से आशा की जाती थी कि अर्थव्यवस्था में स्थिरता होगी और स्वदेशी के साथ-साथ विदेशी निवेश भी भारी मात्रा में आएगा। कुल निवेश बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था चल निकलेगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि बीते पांच साल में यह मन्त्र सफल नहीं हुआ है। वित्तीय घाटा लगातार कम होने के बावजूद अर्थव्यवस्था की विकास दर नहीं बढ़ी है। निवेश में भी वृद्धि नहीं हुई है। बल्कि हाल में प्रकाशित आंकड़े बताते हैं कि पिछले वर्ष 2018-19 में कुल विदेशी निवेश में मामूली गिरावट आई है। इसलिए वित्तीय घाटे पर नियंत्रण के मन्त्र पर पुनर्विचार करना जरूरी है। जैसा ऊपर बताया गया है वित्तीय घाटा वह रकम होती है जो सरकार अपनी आय से अधिक खर्च करती है और जिस खर्च को करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा नोट छापे जाते हैं। सरकार के खर्च दो प्रकार के होते हैं-चालू खर्च एवं पूंजी खर्च। चालू खर्च में सरकारी कर्मियों के वेतन, न्याय व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, मुद्रा व्यवस्था आदि जो रोजमर्रा के खर्च होते हैं, वे शामिल होते हैं। इसके इतर पूंजी खर्च वे होते हैं जो नये निवेश के लिए किये जाते हैं। जैसे हाईवे या एयरपोर्ट बनाने अथवा जनता को मुफ्त वाईफाई उपलब्ध कराने के उपकरण लगाने इत्यादि में। वित्तीय घाटे के निर्धारण में यह नहीं देखा जाता कि सरकार द्वारा इन दोनों में से कौन से खर्च किये जा रहे हैं। सरकार यदि अपने कर्मियों को बढ़ाकर वेतन दे और इसके लिए ऋण ले अथवा सरकार हाईवे बनाने के लिए ऋण ले, दोनों ही हालात में वित्तीय घाटा बढ़ता है। वित्तीय घाटे को इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि खर्च सरकारी खपत के लिए बढ़ रहे हैं अथवा निवेश के लिए। लेकिन किस प्रकार के खर्च के लिए वित्तीय घाटा बढ़ रहा है, इसका अर्थव्यवस्था पर मौलिक प्रभाव पड़ता है। पूंजी और चालू घाटे का अंतर एक उदाहरण से समझा जा सकता है। एक व्यक्ति यदि दुकान समय से पहुंचने के लिए बाइक खरीदने के लिए लोन लेता है तो यह पूंजी खर्च कहा जायेगा। पूंजी खर्च से हुए लाभ से वह लिए गए ऋण का रीपेमेंट कर सकता है। लेकिन यदि विदेशी पर्यटन के लिए वही ऋण लिया जाए तो उससे केवल खपत बढ़ती है और आय नहीं बढ़ती। ऐसे ऋण का रीपेमेंट करना कठिन हो जाता है। विदेशी पर्यटन के लिए लिया गया ऋण सरकार के चालू घाटे के समान है। अतः जिस प्रकार आम आदमी को बाइक खरीदने के लिए ऋण लेना चाहिए और विदेश यात्रा के लिए नहीं, उसी प्रकार सरकार को पूंजी घाटे के लिए ऋण लेना चाहिए, चालू घाटे के लिए नहीं। पहले चालू खर्चों से हुए वित्तीय घाटे में वृद्धि के परिणाम पर विचार करें। मान लीजिये सरकार ने अपने कर्मियों को बढ़ाकर वेतन दिए और इस कार्य के लिए ऋण लिए। ऐसा करने से महंगाई बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था में अस्थिरता आएगी और निवेश में गिरावट आने की संभावना बनती है। इसके विपरीत यदि सरकारी कर्मियों के वेतन को फ्रीज़ कर दिया जाता है, सरकार का चालू घाटा कम हो जाता है तो सरकार को नोट नहीं छापने होंगे, अर्थव्यवस्था में स्थिरता आएगी और विदेशी निवेश के साथ-साथ घरेलू निवेश में वृद्धि होगी। कुल निवेश में वृद्धि होगी और अर्थव्यवस्था के चल निकलने की सम्भावना बनती है। यानी चालू घाटे का बढ़ना नुकसानदेह है और चालू घाटे का घटना लाभप्रद है। पूंजी घाटे के परिणाम इसके पूर्णतया विपरीत होते हैं। मान लीजिये सरकार ने हाईवे बनाने के लिए नोट छापे, पूंजी घाटा बढ़ा और उसके साथ-साथ वित्तीय घाटा भी बढ़ा। नोट छापने से महंगाई बढ़ी, अर्थव्यवस्था में अस्थिरता पैदा हुई। ऐसे में निवेशकों के सामने दो विपरीत प्रभाव सामने आते हैं। एक तरफ उन्हें यह दिखता है कि देश में हाईवे बन रहे हैं और व्यापार करना सुगम हो रहा है। दूसरी तरफ उन्हें यह भी दिखता है कि महंगाई बढ़ रही है और अर्थव्यवस्था में अस्थिरता आ सकती है। अतः निजी निवेश पर कुल प्रभाव सकारात्मक अथवा नकारात्मक दोनों हो सकता है। लेकिन पूंजी खर्चों के लिए किये गए सरकारी खर्च का सीधा सकारात्मक प्रभाव होगा। इसलिए पूंजी खर्चों को पोषित करने के लिए पूंजी घाटे एवं तदनुसार वित्तीय घाटे के बढ़ने से कुल निवेश बढ़ता है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि वर्ष 2014 के पहले अपना वित्तीय घाटा ज्यादा रहता था लेकिन आर्थिक विकास दर भी ऊंची थी। कारण यह था वित्तीय घाटे के कारण उत्पन्न हुई अस्थिरता की तुलना में निवेशकों ने वित्तीय घाटे से पोषित हाईवे को ज्यादा महत्व दिया और निवेश जारी रखा। इसके विपरीत 2014-19 में पूंजी घाटा रहा और वित्तीय घटा कम होता गया। अर्थव्यवस्था स्थिर रही। महंगाई काबू में रही। आशा की जाती थी कि निवेश आएगा लेकिन सरकारी पूंजी खर्च के अभाव में उसका आना संदिग्ध बना रहा। इसलिए हमने देखा है कि पिछले पांच वर्षों में वित्तीय घाटे में लगातार गिरावट के बावजूद निवेश में वृद्धि नहीं हुई और आर्थिक विकास दर सपाट है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि समस्या वितीय घाटे की नहीं बल्कि चालू घाटे की है। चालू घाटे के बढ़ने से अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है जबकि पूंजी घाटे के बढ़ने से अर्थव्यवस्था को लाभ होता है। समस्या यह है कि वित्तीय घाटे में दोनों को जोड़ दिया जाता है। अतः वित्तीय घाटा कम हो लेकिन उसके नियंत्रण के पीछे पूंजी घाटे में कटौती हो तो वह कम होता वित्तीय घाटा नुकसानदेह सिद्ध होता है। जैसा कि पिछले पांच वर्षों में होता रहा है। आने वाली सरकार के वित्त मंत्री के सामने चुनौती है कि सरकार के खर्चों को वित्तीय घाटे के मापदंड से मापने के स्थान पर चालू घाटे के मापदंड से ऊपर नापें। चालू घाटे का नियंत्रण और पूंजी घाटे में वृद्धि ही आर्थिक विकास की सही कुंजी है, जिसे नये वित्त मंत्री को अपनाना चाहिए।

लेखक आर्थिक मामलों के जानकार हैं।

ट्वीट

अंतर

कृपया एंग्लो-इंडियन और भारतीय ईसाइयों के बीच अंतर को लेकर भ्रमित न हों। एंग्लो-इंडियन वे परिवार थे, जिनमें पति-पत्नी में एक भारतीय और दूसरा ब्रिटिश होता था। पति भारतीय तो पत्नी ब्रिटिश या पत्नी भारतीय तो पति ब्रिटिश। भारतीय ईसाइयों में यह बात लागू नहीं होती।

यशवंत देशमुख, चुनाव विश्लेषक

ज्ञान गंगा

युवा

ओशो/ पहली तो बात, युवक हैं कहां? इस देश में तो नहीं हैं। इस देश में तो बच्चे बूढ़े ही पैदा होते हैं; गायत्री मंत्र पढ़ते हुए ही पैदा होते हैं। कोई गीता का पाठ करते चले आ रहे हैं! कोई राम-नाम जपते चले आ रहे हैं! इस देश में युवक हैं कहां? शक्ल-सूरत से भला युवक मालूम पड़ते हों, मगर युवक होना शक्ल-सूरत की बात नहीं। युवक होना उम्र की बात नहीं। युवक होना एक बड़ी और ही, बड़ी अनूठी अनुभूति है एक आध्यात्मिक प्रतीत है! सभी युवक, युवक नहीं होते। सभी बूढ़े, बूढ़े नहीं होते। जिसे युवक होने की कला आती है, वह बूढ़ा होकर भी युवक होता है। और जिसे युवक होने की कला नहीं आती, वह युवक होकर भी बूढ़ा ही होता है। तो पहले तो इस सत्य को समझने की कोशिश करो कि युवा होना क्या है! तुम्हारी उम्र पच्चीस साल है, इसलिए तुम युवा हो, इस भ्रांति में मत पड़ना। उम्र से क्या वास्ता? पच्चीस साल के भला होओ, लेकिन तुम्हारी धारणाएं क्या है? तुम्हारी धारणाएं तो इतनी पिटी-पिटाई हैं, इतनी मुर्दा हैं, इतनी सड़ी-गली हैं, इतनी सदियों से तुम्हारे ऊपर लदी हैं-तुम्हें उन्हें उतारने का भी साहस नहीं है। तुम जंजीरों को आभूषण समझते हो। और तुम, जो बीत चुका, अतीत, उसमें जीते हो। और फिर भी अपने को युवा मानते हो? युवा हो; और पूजते हो जो मर गया उसको! जो बीत गया उसको! जो जा चुका उसको! तुम्हारी धारणाओं का जो स्वर्ण-युग था वह अतीत में था, तो तुम युवा नहीं हो। राम- राज्य, सतयुग सब बीत चुके। वही तुम्हारी श्रद्धा है। लेकिन न तुम विचार करते हो, न तुम श्रद्धा के कभी भीतर प्रवेश करते हो कि श्रद्धा है भी, या सिर्फ थोथा एक आवरण है? पक्षी तो कभी का उड़ गया, पिंजड़ा पड़ा है। तुम कुछ भी मानते चले जाते हो! इतने अंधेपन में युवा नहीं हो सकते। जैसे उदाहरण के लिए, कोई ईसाई कहे कि मैं युवा हूं और फिर भी मानता हो कि जीसस का जन्म कुंवारी मरियम से हुआ था, तो मैं उसे युवा नहीं कह सकता। ऐसी मूढ़तापूर्ण बात, कुंवारी मरियम से कैसे जीसस का जन्म हो सकता है? अगर तुम मान सकते हो, तो तुम अंधे आदमी हो, तुम्हारे पास विवके ही नहीं है, उसके पास श्रद्धा क्या खाक होगी! जिसके पास संदेह की क्षमता नहीं है, उसके पास श्रद्धा की भी संभावना नहीं होती। लेकिन तुम्हारे पंडित-पुरोहित तुम्हें समझाते हैं संदेह न करना। हम जो कहें, मानना। और वे ऐसी-ऐसी बातें कहते हैं तुमसे कि तुम भी जरा सा सजग होओगे तो नहीं मान सकोगे।

उम्मीदों पर खरा उतरने की चुनौती

महिला अधिकार संरक्षण/ अनूप भटनागर

'सबका साथ, सबका विकास' और 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' जैसे नारे के साथ दोबारा सत्तासीन हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली नयी सरकार को देश-दुनिया की तमाम चुनौतियों की रूपरेखा तैयार करते समय देश की महिलाओं को समुचित सुरक्षा प्रदान करना और उनके हितों की रक्षा के मुद्दे को भी प्राथमिकता देनी होगी। महिलाओं के हितों की रक्षा के मामले में दो मुद्दे सबसे अधिक प्रमुख हैं - पहला, संसद और विधानमंडलों में महिलाओं की भागीदारी 33 प्रतिशत करने संबंधी संविधान संशोधन विधेयक को कानूनी रूप दिलाना और दूसरा, मुस्लिम समाज में प्रचलित तीन तलाक की कुप्रथा से मुस्लिम महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिये इसे दंडनीय अपराध बनाने संबंधी प्रक्रिया को कानूनी रूप प्रदान करना। विभिन्न दलों से 78 महिलायें चुनाव जीतकर इस बार लोकसभा पहुंची हैं। महिला प्रतिनिधियों की यह संख्या अब तक लोकसभा पहुंचने वाली महिला सांसदों में सर्वाधिक है। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि ये महिला सांसद दलगत राजनीति से ऊपर उठकर महिलाओं के हितों की रक्षा के लिये इन दोनों कानूनों को अमलीजामा पहनाने के लिये सरकार और अपने दलों पर कारगर तरीके से दबाव बनाने में सफल होंगी।

संसद और विधानमंडलों में महिलाओं के लिये 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने संबंधी 108वां संविधान संशोधन विधेयक नौ साल पहले मई 2010 में राज्यसभा ने पारित किया था। लेकिन 15वीं लोकसभा के कार्यकाल के दौरान राजनीतिक दलों की तमाम आपत्तियों को देखते हुए तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार इसे लोकसभा में पेश करने का साहस नहीं जुटा सकी। अब नौ साल बीत चुके हैं और यह विधेयक अभी तक लोकसभा से पारित नहीं कराया जा सका है। यह भी कहा जा सकता है कि 15वीं और 16वीं लोकसभा में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इसे पारित कराने की मांग ही नहीं की गयी। हां, 16वीं लोकसभा के अंतिम सत्र के दौरान महिला आरक्षण का मुद्दा सदन में उठा लेकिन ऐसा लगता है कि यह सिर्फ रस्म अदायगी ही थी। लेकिन चुनाव के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष ने इस विषय को दबी जुबान में उठाया था। नयी लोकसभा में चूंकि पहली बार सर्वाधिक 78 महिलायें निर्वाचित होकर पहुंची हैं, इसलिए आशा की जानी चाहिए कि महिलाओं के हितों की रक्षा से जुड़ा यह विधेयक पारित कराने के लिये ये सरकार पर दबाव बनायेंगी। जहां तक तीन बार तलाक कह देने के चलन को अपराध के दायरे में लाने का मुद्दा है तो राजग सरकार ने इस संबंध में लोकसभा से मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक पारित कराया था लेकिन इस विधेयक को राज्यसभा से पारित नहीं कराया जा सका। 16वीं लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने के साथ ही यह विधेयक भी निष्प्रभावी हो गया। तीन तलाक को कानून के दायरे में लाने संबंधी इस विधेयक को पारित कराने के लिये सरकार को अब नये सिरे से कदम उठाने होंगे। लोकसभा में तो इस विधेयक को पारित कराने में उसे दिक्कत नहीं होगी लेकिन पिछली बार की तरह ही राज्यसभा में बहुमत नहीं होने की वजह से उसे एक बार फिर चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। राज्यसभा से विधेयक पारित कराने में सफलता नहीं मिलने की वजह से सरकार को इसे पारित कराने के लिये नये सिरे से कदम उठाने होंगे। राजग सरकार ने 2017 में पहली बार मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2017 लोकसभा से पारित कराया था। लोकसभा में इस विधेयक का कांग्रेस ने भी समर्थन किया था लेकिन राज्यसभा में कांग्रेस के जबरदस्त विरोध की वजह से मुस्लिम महिलाओं को एक बार में तीन तलाक अर्थात तलाक-ए बिद्दत के दंश से बचाने के लिये कानून बनाने की कवायद विफल हो गयी थी। इसके बाद सरकार ने तलाक-ए-बिद्दत को अपराध की श्रेणी में रखने और इसे दंडनीय अपराध बनाने के लिये तीन बार अध्यादेश जारी किये थे। उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ पहले ही एक बार में तीन तलाक देने के कृत्य को गैरकानूनी, अनैतिक और महिलाओं की गरिमा के खिलाफ करार दे चुकी है। लोकसभा से इस संबंध में विधेयक पारित होने के बाद तीन तलाक दंडनीय अपराध बन गया। राज्यसभा से विधेयक पारित कराने में सफलता नहीं मिलने पर इस साल फरवरी में तीसरी बार सरकार अध्यादेश लायी थी। उम्मीद की जानी चाहिए कि महिलाओं के लिये आरक्षण और मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक के दंश से बचाने संबंधी विधेयकों को पारित कराकर कानूनी दर्जा दिलाने में नयी सरकार सफल होगी।

आज का राशिफल

मेष व्यावसायिक योजना सफल होगी। किया गया परिश्रम सार्थक होगा। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी। ससुराल पक्ष से लाभ होगा। धार्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि होगी।

वृषभ बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। रुका हुआ कार्य सम्पन्न होगा। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। वाहन प्रयोग में सावधानी रखें। धन लाभ होगा।

मिथुन पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। वाणी पर नियंत्रण रखकर वाद विवाद की स्थिति को टाला जा सकता है। संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा।

कर्क आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा। व्यावसायिक योजना सफल होगी। भाग्यवश कुछ ऐसा होगा जिसका आपको लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य शिथिल होगा। विरोधी परास्त होंगे। व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी।

सिंह प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग हैं। उदर विकार या त्वचा के रोग से पीड़ित रहेंगे। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। अधीनस्थ कर्मचारी से तनाव मिलेगा। प्रणय संबंध प्रगाढ़ होंगे।

कन्या दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। जीवनसाथी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। आय और व्यय में संतुलन बना कर रखें। खान पान में संयम रखें। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी।

तुला आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी। आय और व्यय में संतुलन बना कर रखें। प्रणय संबंधों में कटुता आ सकती है। विरोधियों का पराभव होगा।

वृश्चिक आर्थिक दिशा में किए गए प्रयास सफल होंगे। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। नेत्र विकार की संभावना है। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।

धनु पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। भाई या पड़ोसी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। ससुराल पक्ष से लाभ मिलेगा। धन लाभ की संभावना है।

मकर पारिवारिक जनों का सहयोग मिलेगा। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। स्थानान्तरण व परिवर्तन के योग हैं। आय के नवीन स्त्रोत बनेंगे।

कुम्भ शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। धार्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि होगी।

मीन पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। वाणी पर नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। मनोरंजन के अवसर प्राप्त होंगे। वाहन प्रयोग में सावधानी रखें।

जेट एयरवेज की असफलता से इंडस्ट्री और नीति निर्माताओं की आंखें खुल जानी चाहिए : अजय सिंह

सिओल:

निजी क्षेत्र की एयरलाइन जेट एयरवेज का धराशायी होना सभी के लिए नींद से जागने का समय है और इसका कुछ न कुछ दोष नीति निर्माताओं का भी है क्योंकि देश में लागत ढांचा काफी ऊंचा है। स्पाइसजेट के प्रमुख अजय सिंह ने यह कहा है। सस्ती विमानन कंपनी स्पाइसजेट अपने कारोबार का विस्तार कर रही है और वह 30 विमानों को पट्टे पर लेने की तैयारी में है। इन विमानों का इस्तेमाल जेट एयरवेज करती रही है। उल्लेखनीय है कि जेट एयरवेज ने अप्रैल में नकदी संकट के चलते उड़ान परिचालन को निलंबित कर दिया था। स्पाइसजेट के बेड़े में अब कम-से-कम 100 विमान शामिल हैं। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की सालाना आम बैठक के दौरान अलग से बातचीत में स्पाइसजेट के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक ने कहा कि हम जेट एयरवेज के 2,000 कर्मचारियों को नियुक्त करने की भी योजना बना रहे हैं। एयरलाइन पहले ही 1,100 से अधिक ऐसे लोगों को नियुक्त कर चुकी है। जेट एयरवेज की उड़ानें बंद होने को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए सिंह ने कहा कि आंतरिक कारण और ऊंची लागत इस असफलता के कारणों में शामिल हैं। उन्होंने कहा, ''जेट एयरवेज का जमीन पर खड़ा होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और यह विमानन क्षेत्र में काम करने वाले हम सभी के लिए और नीति निर्माताओं के लिए नींद से जगाने वाला है। मेरा मानना है कि जेट एयरवेज एक बेहतर ब्रांड रहा है और इसकी असफलता का कम से कम कुछ दोष तो नीति निर्माताओं का भी है। सिंह ने कहा, ''विमानन क्षेत्र के लिए लागत ढांचा काफी ऊंचा है। जेट एयरवेज की असफलता में इसका काफी योगदान रहा। इसके साथ ही आंतरिक कारण भी रहे हैं। यह सच्चाई रही है कि जेट का लागत ढांचा संभवतः प्रतिस्पर्धी नहीं था और जैसे-जैसे और एयरलाइन आई उसके लिए लागत ढांचे के साथ कमाई करना मुश्किल होता चला गया। जेट एयरवेज ने 26 साल तक विमानन क्षेत्र में संचालन किया।

वोडाफोन आइडिया ने पंजाब में रेडियो नेटवर्क का सफल कॉन्सोलिडेशन किया

जालंधर:

भारत के अग्रणी दूरसंचार सेवा प्रदाता वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने पंजाब सेवा क्षेत्र में अपने रेडियो नेटवर्क कॉन्सोलिडेशन के सफल समेकन की घोषणा की है। इसके साथ ही पंजाब उन पहले दस सर्कल्स में से एक बन गया है, जहां विश्व के सबसे बड़े नेटवर्क कॉन्सोलिडेशन अभ्यास में संपूर्ण कॉन्सोलिडेशन हुआ है, जो वर्तमान में भारत में जारी है। पंजाब वोडाफोन और आइडिया के लिए सबसे मजबूत बाजारों में से एक था और कॉन्सोलिडेशन के बाद यह मजबूत एकीकृत नेटवर्क बन गया है।

साइट्स की अधिक संख्या और प्रत्येक ब्राण्ड के लिए स्पेक्ट्रम के बड़े आवंटन के साथ नेटवर्क क्षमता बढ़ी है, जिससे नेट प्रमोटर स्कोर बेहतर हुआ है और सर्कल में दोनों ब्राण्ड्स के यूजर्स के लिए डाउनलोड स्पीड अधिक तीव्र हुई है। कॉन्सोलिडेशन के बाद वोडाफोन आइडिया का 4जी कवरेज 24 जिलों की लगभग 90 प्रतिशत जनसंख्या को कवर कर रहा है, जहां पंजाब के 227 कस्बे और 10162 गांव हैं। कंपनी नई प्रौद्योगिकी भी लगा रही है, जैसे मैसिव मीमो, स्मॉल सेल्स और टीडीडी, ताकि इस क्षेत्र में कवरेज और नेटवर्क क्षमता बढ़े। इससे वोडाफोन आइडिया के उन ग्राहकों का 4जी अनुभव उन्नत हुआ है, जो अब सभी प्रमुख शहरों में अपने 4जी नेटवर्क पर दोगुनी तेज गति का आनंद ले रहे हैं, जैसे चंडीगढ़, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, पटियाला, बठिंडा, मोगा, होशियारपुर, आदि। पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अनुसार, ''पंजाब सर्कल में नेटवर्क के सफलकॉन्सोलिडेशन से वोडाफोन आइडिया के लगभग 11 मिलियन ग्राहक 2जी, 3जी और 4जी पर एकीकृत नेटवर्क का अनुभव ले सकते हैं।

देशभर में गेहूं की सरकारी खरीद 337 लाख टन, पिछले साल से 1.7 फीसदी कम

नई दिल्ली ।

देशभर में गेहूं की सरकारी खरीद चालू रबी विपणन वर्ष (2019-20) में अब तक 337 लाख टन पूरी हुई है, जबकि पिछले साल इस दौरान सरकारी एजेंसियों ने किसानों से 343 लाख टन गेहूं खरीदा था। इस प्रकार पिछले साल के मुकाबले चालू सीजन में गेहूं की सरकारी खरीद 1.74 फीसदी कम हुई है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) की ओर से मंगलवार को मिली जानकारी के अनुसार, चालू सीजन में देशभर में सरकारी एजेंसियों ने अब तक 337 लाख टन गेहूं सीधे किसानों से खरीदा है, जबकि पिछले साल इसी अवधि के दौरान 343 लाख टन गेहूं की खरीद हुई थी। एफसीआई से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, पंजाब में सबसे ज्यादा 129.12 लाख टन गेहूं की खरीद हुई है, जबकि पिछले साल 126 लाख टन की खरीद हुई थी। हरियाणा में सरकारी एजेंसियों ने 93.23 लाख टन गेहूं खरीदा है, जबकि पिछले साल 87 लाख टन खरीदा गया था। मध्य प्रदेश में गेहूं की खरीद 67.25 लाख टन हुई है जबकि पिछले साल प्रदेश में 69.67 लाख टन गेहूं खरीदा गया था। देश के सबसे बड़े गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में इस साल अब तक 33.79 लाख टन गूेहं की खरीद हो पाई है, जबकि पिछले साल इस दौरान 43.58 लाख टन गेहूं की सरकारी खरीद हुई थी। एफसीआई के सूत्रों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में अब तक खरीद चालू है, जबकि अन्य जगहों पर खरीद तकरीबन समाप्त हो चुकी है। वहीं, राजस्थान में सरकारी एजेंसियों ने इस साल 13 लाख टन गेहूं खरीदा है जबकि पिछले साल इसी दौरान वहां 14.96 लाख टन की खरीद हुई थी। एफसीआई के आंकड़ों के अनुसार, उत्तराखंड में इस साल 41,787 टन, चंडीगढ़ में 12,450 टन, गुजरात में 4650 टन और हिमाचल प्रदेश में 1,000 टन गेहूं की सरकारी खरीद हुई है।

जियो का क्रिकेट प्रेमियों को तोहफा, मुफ्त में देखें विश्व कप क्रिकेट मैच

नयी दिल्ली ।

रिलायंस जियो ने क्रिकेट प्रेमियों को खास तोहफा देते हुए अपने ग्राहकों को विश्व कप क्रिकेट 2019 के सभी मैच मोबाइल फोन पर सजीव देखने का मौका उपलब्ध कराया है। कंपनी की यहां जारी विज्ञप्ति के अनुसार कोई भी जियो से जुड़ा उपभोक्ता जियो टीवी ऐप या फिर हॉटस्टार ऐप पर मुफ्त में विश्व कप मैचों का सजीव प्रसारण देख सकेगा। जियो ने इसके लिए हॉटस्टार के साथ साझेदारी की है। इसके लिए उपभोक्ता के मोबाइल फोन में जियो का सिम कार्ड होना जरूरी है। कंपनी ने क्रिकेट विश्व कप 2019 को लेकर खास पैक भी पेश किया है जिसकी कीमत 251 रुपये है। इस पैक से लाभ यह होगा कि फोन का मौजूदा पैक खत्म हो जायें तो भी मैच का सजीव प्रसारण देखा जा सकेगा। इस पैक की वैधता 51 दिनों की है जिसमें 102 जीबी डाटा मिलेगा।

संक्षिप्त समाचार

सोना-चांदी चमके, तीन सप्ताह के उच्चतम स्तर पर

नई दिल्ली: विदेशी बाजारों में सोने-चांदी के तीन महीने से अधिक के उच्चतम स्तर पर पहुंचने से दिल्ली सर्राफा बाजार में मंगलवार को सोना 175 रुपए चमककर तीन सप्ताह के उच्चतम स्तर 33,370 रुपए प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया। चांदी भी 250 रुपए उछलकर करीब तीन सप्ताह के उच्चतम स्तर 37,750 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही। वैश्विक स्तर पर सोमवार को सोना 1,327.90 डॉलर प्रति औंस को छूने में कामयाब रहा था जो इस साल 27 फरवरी के बाद का उच्चतम स्तर है। मंगलवार को हालांकि यह 1.40 डॉलर की गिरावट में 1,323.20 डॉलर प्रति औंस पर रहा। अगस्त का अमेरिकी सोना वायदा आज भी एक डॉलर की बढ़त में 1,328.90 डॉलर प्रति औंस बोला गया। बाजार विश्लेषकों ने बताया कि वैश्विक स्तर पर व्यापार युद्ध गहराने के कारण निवेशक पूंजी बाजार की बजाय सुरक्षित निवेश मानी जानी वाली पीली धातु का रुख कर रहे हैं। इससे सोने की कीमतों में तेजी आई है।

वैश्विक स्मार्टफोन की बिक्री 2019 में 3.1 फीसदी घटी

शंघाई । अमेरिकी सरकार द्वारा हुआवेई के साथ व्यापार पर प्रतिबंध लगाने के फैसले के बीच वैश्विक स्मार्टफोन बाजार के लिए अपने पूर्वानुमान को 3 फीसदी से अधिक घटाते हुए मार्केट रिसर्च फर्म केनालिस ने कहा है कि 2019 में कुल 1.35 अरब स्मार्टफोन की बिक्री होगी। यह 2018 में हुई स्मार्टफोन्स की कुल 1.39 अरब की बिक्री से कम है। केनालिस ने उपाध्यक्ष मोबिलिटी निकोल पेंग ने एक बयान में कहा, यह ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि बाजार में अनिश्चितता के माहौल के कारण चुनौतीपूर्ण कारोबारी माहौल में विक्रेताओं को अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रभाव को कम करने के लिए कुछ रणनीतियों में तेजी लानी होगी। उन्होंने कहा, लेकिन हाल में ही अमेरिका द्वारा अधिक देशों के सामानों पर शुल्क लगाने के कारण उद्योग को इस उथलपुथल से निपटने में कुछ वक्त लगेगा। रिसर्च फर्म ने कहा कि 2020 में ज्यादातर मोबाइल आपूर्ति श्रृंखला और चैनल सक्रियता से आकस्मिक योजनाएं बना रही हैं, ताकि हुआवेई की गिरावट से खाली हुए बाजारों में 5जी डिवाइसों की आपूर्ति कर सके। भविष्य के प्रति आशावादी रुख अपनाते हुए केनालिस ने साल 2020 में स्मार्टफोन की बिक्री में बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है और कहा कि इस साल दुनिया भर में कुल 1.34 अरब स्मार्टफोन की बिक्री होगी, जो 3.4 फीसदी की बढ़ोतरी है।

ईडी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में कहा- मेहुल चोकसी भगोड़ा और फरार है, उसकी याचिकाएं रद्द हों

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बॉम्बे हाईकोर्ट में हलफनामा दायर कर मेहुल चोकसी की दो याचिकाएं खारिज करने की अपील की है। न्यूज एजेंसी ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। पीएनबी घोटाले के आरोपी चोकसी ने एक याचिका भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की प्रक्रिया के खिलाफ दायर की थी। दूसरी याचिका में कहा था कि ईडी जिन लोगों के बयानों के आधार पर उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करवाना चाहता है उन लोगों से बहस की इजाजत दी जाए। दोनों याचिकाओं पर 10 जून को अगली सुनवाई होगी। ईडी ने हलफनामे में कहा है कि चोकसी पीएनबी घोटाले में 6,097 करोड़ रुपए की रकम का हेर-फेर करने का आरोपी है। उसे जांच के लिए पेश होने के समन जारी किए गए थे लेकिन उसने कहा कि वह सहयोग नहीं करेगा। ईडी ने कहा है कि चोकसी एंटीगुआ की नागरिकता ले चुका है। इससे स्पष्ट होता है कि वह जांच में सहयोग के लिए भारत नहीं आना चाहता। एजेंसी ने यह भी कहा है कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून के तहत विचाराधीन भगोड़ा व्यक्ति कोर्ट में पेश होता है तो कार्रवाई निलंबित भी की जा सकती है लेकिन पेश नहीं होने पर अदालत उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर संपत्ति जब्त कर सकती है।

हालात सुधारने के लिए बैंकों को 40 हजार करोड़ रुपए देगी सरकार, बजट में हो सकता है ऐलान

नई दिल्ली: पब्लिक सेक्टर के बैंकों के हालात सुधारने और प्रॉम्प्ट करेक्टिव ऐक्शन (PCA) फ्रेमवर्क से बाहर निकालने के लिए सरकार उन्हें इस वित्त वर्ष में 40 हजार करोड़ रुपए दे सकती है। इसका ऐलान 5 जुलाई को पेश किए जाने वाले बजट में हो सकता है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सरकार लोन ग्रोथ बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है लेकिन कई कमजोर बैंकों की बैलेंस सीट आड़े आ रही है। बैलेंस शीट कमजोर होने का कारण इन बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पीएसए फ्रेमवर्क में आ जाते हैं जिससे उनके लोन देने पर पाबंदी लग जाती है। इस स्थिति को बदलने के लिए सरकार ने इन बैंकों को 40 हजार करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। इससे बैंकों की बैलेंस शीट में सुधार होगा, साथ ही वह पीसीएम फ्रेमवर्क से बाहर निकलकर लोन देने के काबिल हो जाएंगे।

पिछले साल दिए थे 1.6 लाख करोड़ रुपए

पिछले साल सरकार ने पब्लिक सेक्टर के कई बैंकों को पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर निकालने के लिए रिकॉर्ड 1.6 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया था। इस सरकारी मदद से पांच बैंक पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर आ गए थे।

अमेरिका में जांच के दायरे में फंसी एप्पल

गैजेट डेस्क:

अमेरिका में एक बार फिर एप्पल जांच के घेरे में आ गई है। अमेरिका के न्याय विभाग ने अधिकारियों को एप्पल की एंटी ट्रस्ट नियमों की जांच करने का अधिकार दिया है। मीडिया रिपोट्र्स के अनुसार, गूगल न्याय विभाग अविश्वास जांचकर्ताओं की निगरानी में है। बताया जाता है कि **DOJ** इसके विज्ञापन और खोज कारोबार पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसी दौरान संघीय व्यापार आयोग ने फेसबुक और अमेजॉन की जांच करने के लिए अधिकृत किया गया है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि न्याय विभाग ने एप्पल के संबंध में क्या कार्रवाई की है और अविश्वासनीय मामले पर क्या ध्यान केंद्रित होगा। मौजूदा समय में यूरोपिय संघ में एप्पल के खिलाफ जांच चल रही है जहां स्ट्रीमिंग म्यूजिक प्रदाता **Spotify** ने कंपनी पर आरोप लगाया है कि वह अपनी म्यूजिक एप का पक्ष ले रहा है और एप्प स्टोर फीस के साथ **Spotify** की कीमतों से वंचित कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने व्यवस्था दी थी कि उसे आईफोन एप्प खरीदारों द्वारा किए गए अविश्वसनीय मुकद्दमें का सामना करना पड़ेगा। यह कई वर्ष पूर्व ईबुक प्राइस-फिक्सिंग एंटीट्रस्ट मामले में भी शामिल है। अंततः उसे उपभोक्ताओं को रिफंड करना पड़ा जिन्होंने पुस्तकों के लिए अधिक राशि दी थी। सीनेटर एलिजाबेथ वारेन ने टेक कंपनियों की सूची में एप्पल को शामिल किया और कंपनी के एप्प स्टोर से बटने से एप्पल का मामला टूट जाना चाहिए। सीनेटर एलिजाबेथ वारेन ने इस वर्ष के शुरू में कहा था कि वह या तो मंच का संचालन करें या फिर वह स्टोर में काम करें। वह एक ही समय में दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते है।

सिलेंडर विस्फोट में मृतक के परिजनों को 12 लाख रुपए का मुआवजा देने का एनसीडीआरसी का निर्देश

नई दिल्ली:

शीर्ष उपभोक्ता आयोग ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि. (आईओसीएल) तथा उसके डीलर को सिलेंडर विस्फोट में मारी गई महिला के परिजनों को 12 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग (एनसीडीआरसी) ने कहा कि यह दुर्घटना विनिर्माण की खामी की वजह से हुई।

कंपनी और डीलर जिम्मेदार: NCRDC

एनसीडीआरसी ने इस दुर्घटना के लिए आईओसीएल तथा आलोक गैस एजेंसी को जिम्मेदार ठहराया है। इस हादसे में गृहणी नीना झांब की मृत्यु हो गई थी जबकि उनकी सास गंभीर रूप से घायल हुई थीं। आयोग ने कहा कि इस खामी की जांच करने की जिम्मेदारी आईओसीएल की है क्योंकि इस बात के कोई प्रमाण नहीं हैं कि उपभोक्ता की ओर से कोई लापरवाही बरती गई।

मैन्युफैक्क्रिंग फॉल्ड के कारण हुआ विस्फोट: NCRDC

आयोग ने अपने हालिया आदेश में कहा कि विनिर्माता होने की वजह से जिम्मेदारी आईओसीएल की बनती है कि वह जांच करे और खामी के बारे में रिपोर्ट दे। ऐसा नहीं किया गया। ऐसे में आईओसीएल की यह दलील कि मैन्युफैक्क्रिंग डिफॉल्ट की कोई रिपोर्ट नहीं है, को स्वीकार नहीं किया जा सकता। एनसीडीआरसी के अध्यक्ष आर के अग्रवाल तथा सदस्य एम श्रीश ने कहा कि इस मामले का दायित्व आईओसीएल और डीलर दोनों का बनता है। रिकॉर्ड पर जो दस्तावेज हैं उनके मुताबिक सिलेंडर में विस्फोट मैन्युफैक्क्रिंग डिफॉल्ट की वजह से हुआ। इसकी मुख्य जिम्मेदारी आईओसीएल की है।

IOCL, एजेंसी और बीमा कंपनी को झटका

एनसीडीआरसी ने यह आदेश आईओसीएल, गैस एजेंसी तथा बीमा कंपनी की अपील पर दिया है। इन्होंने मृतक के परिजनों को 12 लाख 21 हजार 734 रुपये ब्याज के साथ देने के दिल्ली राज्य उपभोक्ता मंच के आदेश को चुनौती दी थी। आयोग ने अपील को खारिज करते हुए आईओसीएल को केस की लागत का 25 हजार रुपये देने का भी निर्देश दिया है। आईओसीएल के खिलाफ यह शिकायत मृतका के पति और बच्चों ने दायर की थी। शिकायत में कहा गया था कि तीन अप्रैल 2003 को नीना जब रसोई में खाना बना रही थीं तो सिलेंडर फटने से उनकी मृत्यु हो गई। इस हादसे मे नीना की सास कान्ता घायल हो गईं।

गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बजार, सेंसेक्स 184 अंक फिसला

नई दिल्लीः एक दिन पहले रिकॉर्ड बनाने के बाद मंगलवार को भारतीय बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 184.08 अंकों की गिरावट के साथ 40083.54 और निफ्टी 66.90 अंक फिसलकर 12021.65 अंक पर बंद हुआ। बंबई स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 132 अंकों की गिरावट के साथ 40,153 अंकों पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का 50 शेयरों का संवेदी सूचकांक निफ्टी 37 अंकों की गिरावट के साथ 12,051 अंकों पर खुला। सुबह 9.26 बजे सेंसेक्स 27 अंकों की गिरावट के साथ 40,240 अंकों पर और निफ्टी 1 अंक की तेजी के साथ 12,089 अंकों पर कारोबार कर रहे हैं।

शेयरों का हाल

मंगलवार को शुरुआती कारोबार में विप्रो, डॉ. रेड्डीज लेब, इंडियाबुल्स हाउसिंग, पीएफसी, एनटीपीसी, एलएंडटी, आईटीसी और टाइटन में तेजी का माहौल है। वहीं, टीसीएस, जी एंटरटेनमेंट, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचसीएल टेक्नोलॉजी, बीपीसीएल, एचपीसीएल में मंदी का माहौल है।

प्याज कीमत को कम रखने के लिए 50 हजार टन का बफर स्टॉक बनाएगी सरकार

बिजनेस डेस्क:

केंद्र ने प्याज उत्पादक राज्यों में सूखे जैसी स्थिति के मद्देनजर आने वाले महीनों में इस महत्वपूर्ण फसल की कीमत पर अंकुश रखने के लिए 50,000 टन प्याज का बफर स्टॉक बनाना शुरू कर दिया है। खाद्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, एशिया में प्याज की सबसे बड़ी थोक मंडी महाराष्ट्र के लासलगांव में इसका थोक भाव 29 प्रतिशत बढ़कर 11 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। पिछले साल इसी दौरान भाव 8.50 रुपए का था। दिल्ली में खुदरा प्याज 20 से 25 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रही है। अधिकारी ने कहा, ÷उत्पादक क्षेत्र में सूखे की स्थिति के कारण, रबी की प्याज का उत्पादन कम होने की संभावना है। इससे इसकी आपूर्ति व भाव, दोनों पर दबाव बढ़ सकता है।÷ सहकारी संस्था, नाफेड को मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत प्याज की खरीद करने के लिए कहा गया है, उसने अब तक रबी की लगभग 32,000 टन रबी की एसी किस्मों की प्याज खरीदी है जिनको जमा कर के कुछ समय के लिए रखा जा सकता है। इस भंडा को जुलाई के बाद नई आपूर्ति न होने के समय इस्तेमाल में लाया जा सकता है।

महाराष्ट्र, कर्नाटक सूखे की चपेट में

अधिकारी ने कहा कि प्याज के अलावा सरकार इस वर्ष दलहन के लिए भी 16.15 लाख टन का बफर स्टॉक बना रही है। इस वर्ष महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे प्रमुख प्याज उत्पादक राज्य सूखे की स्थिति से गुजर रहे हैं। पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार जून में समाप्त होने वाले चालू फसल वर्ष 2018-19 में प्याज उत्पादन थोड़ा अधिक यानी दो करोड़ 36.2 लाख टन होने का अनुमान है जो उत्पादन वर्ष 2017-18 में दो करोड़ 32.6 लाख टन था। सरकार के द्वारा सूखे के प्रभाव के कारण अनुमान को संशोधित किए जाने की उम्मीद है। भारत के प्याज उत्पादन का 60 प्रतिशत भाग रबी का होता है जिसकी खुदाई लगभग पूरी हो चुकी है। भारत में प्याज तीन बार, खरीफ (गरमी), देर खरीफ और रबी (जाड़े) के सीजन में लगाई जाती है।

तालुका हेल्थ आफिस कामरेज एवं कामरेज तालुका के सभी प्राथमिक आरोग्य केन्द्रों द्वारा विश्व तम्बाकू निषेध दिन मनाया

सूरत। मंगलवार को हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 31 मई को समस्त विश्व में विश्व तम्बाकू निषेध दिवस की विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा मना कर जन जागृति से सम्बन्धित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। जिसके अन्तर्गत कामरेज तालुका में मुख्य जिला आरोग्य अधिकारी श्री डा. हसमुख चौधरी तथा सूरत के इ.एम.ओ. श्री डा. पीयुष शाह के मार्गदर्शन के तहत कामरेज तालुका के प्रा. आ. केन्द्र आरोणा सेवणी, नवी पारड़ी, वलण एवं वाव में कामरेज तालुका के इन्चार्ज तालुका हेल्थ आफीसर श्री डा. कौशिक महेता के नेतृत्व के तहत विश्व तम्बाकू निषेध दिन का उत्सव मनाया गया। कामरेज तालुका हेल्थ कार्यालय से विश्व तम्बाकू निषेध दिन मनाने हेतु जन जागृति रैली का आयोजन किया गया। इस रैली का प्रस्थान कामरेज तालुका के इंचार्ज तालुका हेल्थ आफीसर डा. कौशिक महेता तथा प्रा.आ.केन्द्र कठोदरा के मेडिकल आफिसर डा. कीर्तिक सोनाविया द्वारा हरी झंडी दिखाकर प्रस्थान कराया गया। विश्व तम्बाकू निषेध दिन उत्सव निमित्त जन जागृति रैली में प्रत्येक उप आरोग्य केन्द्रों के सुपरवायजरों, ए.एन.एम./ फि.हे.व. /म.प.हे.व.एवं आशा फेसेलीटेटरों तथा आशा बहनों ने उत्साहित होकर भाग लिया था। विश्व तम्बाकू निषेध दिन मनाने हेतु जन जागृति रैली कामरेज गाम में फिर रही थी एवं भाइयों बहनों ने हाथ में होर्डिंग एवं बैनर्स लेकर विभिन्न नारे लगाये जैसे कि जिंदगी पसन्द करों नही कि तम्बाकू, बीडी, गुटका छोडो, छोडों छोड़ो, व्यसनों छोड़ों, व्यसन की मजा मौत की सजा ऐसे अनेक नाराओं से लोगों को जागृत कराया था।

सभी पुलिस कर्मचारियों को वर्दी पहनना अनिवार्य पुलिस कमिश्नर शर्मा ने दिया आदेश

सूरत। मंगलवार को खटोदरा पुलिस स्टेशन में आरोपी की हत्या मामले में सूरत पुलिस कमिश्नर सतीश शर्मा द्वारा महत्वपुर्ण आदेश दिया गया है। सूरत पुलिस कमिश्नर के आदेशानुसार किसी भी पुलिस स्टेशन में आरोपी की गिरफ्तारी के बिना लाकअप में न रखे यदि रखा गया तो पी.आई.के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

सूरत पुलिस कमिश्नर सतीष शर्मा द्वारा आदेश दिया गया है कि सभी पुलिस स्टेशनों में एल.आई.बी के आदमियों के सिवाय सभी पुलिस कर्मचारी यूनीफार्म में ड्युटी करेंगे। ओमप्रकाश पान्डेय की कस्टडी में मृत्यु होने के बाद सभी पुलिस स्टेशनों में अब से पी.आई. द्वारा नौकरी का वितरण किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि खटोदरा पी.आई. खिलेरी, पी.एस.आई. चिराग चौधरी, कान्टेवल कल्पेश गरंभा, आशीष दिहोरा, हरेश चौधरी, परेश भूकण, कनक सिंह दियोल के विरुद्ध हत्या का अपराध दर्ज कर सभी की खोजबीन शुरु की गयी है। भाग जाने वालों के सभी मोबाइल फोन पुलिस में जमा होने से पकड़ने का कार्य दुरुह एवं चैलन्जपूर्ण हो गया है।

वराछा में चाय की लारी में तोड़ फोड़ के बाद 18.700 की लूट

वि पान्डेय सहित तीन लोगों के विरुद्ध फरियाद

सूरत। मंगलवार को वराछा चाय की लारी पर सामान्य कारणों से तोड़ फोड़ कर गल्ले में रखे नकद 18.700 रुपये की लूट कर तीन व्यक्ति फरार हो गये ऐसी घटना वराछा पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई है। पुलिस ने लूट का अपराध दर्ज कर जांच की कार्यवाही शुरु कर दी है।

पुलिस सूत्रों की सूचनानुसार मूल उत्तरप्रदेश के मिरजापुर जिले का निवासी एवं हाल में वराछा ए.के. रोड़ में सुनील भाई राजपुत रहता है। उनकी एक चाय की लारी ए.के. रोड़ सुथारपंच की चाल के पास स्थित है। गतरोड 3 जून के दिन रात्रि में ए.के. रोड़ लाल अखाड़ा के पास रहने वाले रवि पान्डे कालिया एवं एक अज्ञात व्यक्ति ने लारी पर तोड़ फोड़ कर गल्ला में रखे 18.700 नकद की लूट कर फरार हो गये थे। इसके बाद चाय की लारी के सामने रखी आटो रिक्शा को भी नुकसान किया था। वराछा पुलिस ने लूट का अपराध दर्ज कर जांच की कार्यवाही शुरु कर दी है ।

खटोदरा स्थित दर्पण ट्रावेल्स द्वारा 2.70 लाख की ठगाई

ट्रेन की बोगी बुक करने हेतु हुई ये धोखाधड़ी

सूरत। मंगलवार को खटोदरा की दर्पण ट्रावेल्स वाले ने लग्न हेतु तीन चार्टर्ड को बुक करवाने के नाम पर 2.70 लाख रुपये की ठगी की है। सलाबत पुरा पुलिस सूत्रों के अनुसार घोडदौड़ रोड़ रत्न नाम अपार्टमेन्ट निवासी डा. राजेश ईश्वर भाई देसाई ने आरोपी कमल श्रीवास्तव दपर्ण ट्रावेल्स गांधीनगर खटोदरा विरुद्ध शिकायत दर्ज करायी है। शिकायत में कथनानुसार फरियादी की पुत्री के लग्न हेतु सूरत से मडगांव रेल्वे स्टेशन के तीन चार्टर्ड कोच बुक करवाने का विश्वास आरोपी ने दिया था एवं डिपोजिट हेतु टुकडे टुकडे करके 2.70 लाख प्राप्त करने के बाद बुकिंग नहीं कराया और पैसे देने हेतु वायदे करने के बाद भी वायदे कर विश्वासघात एवं धोखाधड़ी की है। पुलिस ने फरियाद दर्ज कर जांच कार्यवाही शुरु कर दी है।

मनपा-डीईओ से मिल रहे नोटिस को लेकर स्कूल दुविधा में है

अहमदाबाद । तक्षशिला आर्केड अग्निकांड बाद मनपा और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से शहर के स्कूलों की जांच शुरू की गई। फायर सेफ्टी सुविधा नहीं होने पर स्कूलों को नोटीस दिया जा रहा है। तीन दिन के अंदर फायर सेफ्टी उपकरण उपलब्ध करवा कर दमकल विभाग से एनओसी लेने का आदेश दिया जा रहा है। दूसरी और कई स्कूलों में अवैध डोम तोड़े जा रहे है। इस कार्रवाई को लेकर स्वनिर्भर शाला संचालक मंडल की बैठक हुई। इसमें कई कड़े फैसले किए गए। तीन दिन में स्कूल एनओसी नहीं होने पर स्कूल को सील करने की चेतावनी दी जा रही है। इस अवधि को बढ़ाने की मांग के साथ संचालक मंडल जिला शिक्षा अधिकारी से मिल चुका है। संचालक मंडल ने तय किया है कि अगर समय अवधि नहीं बढी तो वेकेशन के बाद स्कूलों को नहीं खोला जाएगा। बच्चों की सुरक्षा को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी ने ३५ सदस्यों की टीमो का गठन कर सभी स्कूलों में फायर सेफ्टी की जांच का आदेश किया था। टीम शहर के २०० से अधिक स्कूलों की जांच कर चुकी है। जांच रिपोर्ट प्रतिदिन जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपी जा रही है। फायर सेफ्टी और विद्यार्थियों की सुरक्षा के अभाव पर २० से अधिक स्कूलों को नोटींस तक सीमित रह गई थी। जिला शिक्षा अधिकारी ने ने स्कूलो में फायर सेफ्टी की सुविधा के अलावा बीयूसी, स्ट्रक्चर स्टेबिलीटी रिपोर्ट की भी जांच करने का आदेश दिया था। शहर में ७०० से अधिक स्कूल है। इससे पहले जब जिला शिक्षा अधिकारी को रिपोर्ट सौंपी गई थी, उसमें सिर्फ ५० के पास दमकल विभाग का एनओसी होने का पता चला था। दमकल विभाग ने १८० स्कूलों को नोटिस भेजा था, लेकिन किसी स्कूल पर कार्रवाई नहीं हुई।

अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ७ करोड़ का सोना जब्त

अहमदाबाद । अहमदाबाद एयरपोर्ट पर दुबई से आये एक शख्स के पास ७ करोड़ रुपये की कीमत का २४ किलो सोना पकड़े जाने से सनसनी मच गई। दुबई से आये शख्स ने अपना मालसामान बाहर लाने के लिए ग्राउंड हेन्डलींग स्टाफ की मदद ली, इस दौरान कस्टम अधिकारी को आशंका होने पर उन्होंने यह शख्स को रोका और इसकी चेकिंग के दौरान एक बॉक्स में से २४ किलो सोना जब्त किया गया। कस्टम अधिकारियों ने जिग्नेश नाम के इस शख्स को हिरासत में लेकर इसकी पूछताछ की गई थी। स्थानीय पुलिस ने भी इस मामले में आगे की जांच शुरू कर दी है। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर मंगलवार को दुबई से एक शख्स उतरा था और उन्होंने अपना मालसामान ज्यादा होने से एयरपोर्ट पर ग्राउंड हेन्डलींग स्टाफ की मदद ली और कर्मचारी को कार्गो की ट्रोली रखा जाता है वहां एयरकार्गो का काम करते कर्मचारी को एक बॉक्स दिया। यह पूरे घटना के दौरान एक कस्टम अधिकारी यह सभी देख रहा था और उनको आशंका होने पर उन्होंने यह शख्स को साइड में रोक दिया था और इसकी चेकिंग की गई थी, जिसमें इसके मालसामान से बॉक्स में से २४ किलो सोना जब्त किया गया। कस्टम अधिकारी और स्थानीय पुलिस पुलिस भी इतना ज्यादा सोने का जत्था देखकर आश्चर्यचकित हो गए। प्राथमिक जांच में यह सोने का जत्था ७ करोड़ रुपये की कीमत का होने का माना जा रहा है। कस्टम अधिकारियों ने दुबई से २४ किलो सोना लेकर आये शख्स को हिरासत में लेकर इसकी पूछताछ की गई थी। दूसरी तरफ स्थानीय पुलिस ने भी यह शख्स सोना कहां से लाया था और किसे डीलिवरी करना था, यह खुद इतना ज्यादा सोने का जत्था किसके कहने से लाया था क्या यह सोने की हेराफेरी के लिए कैरियर के तौर पर काम करता था की नहीं यह सहित के मुद्दे पर अब जांच शुरू की गई है।

एएमसी कांग्रेस के सदस्य अचानक वीएस अस्पताल की मुलाकात पर पहुंचे और जानकारी ली गई।

अभिभावक मंडल पेशकश चुडासमा ने खारिज की

स्कूलों में वेकेशन नहीं बढ़ाया जाएगा : शिक्षामंत्री की बात

आगामी १३ से १५ जून के दौरान स्कूल प्रवेशोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा : सरकार का निर्णय

अहमदाबाद । गुजरात सहित देशभर में प्रचंड गर्मी का दौर फिर से आ गया है तब और गर्मी पड़ने की भविष्यवाणी के बीच गुजरातभर की स्कूलों में वेकेशन बढ़ाने के लिए अभिभावक मंडल द्वारा राज्य के शिक्षामंत्री भूपेन्द्रसिंह चुडासमा के समक्ष पेशकश की गई थी। दूसरी तरफ, स्कूल संचालक मंडल द्वारा वेकेशन बढ़ाने के खिलाफ विरोध व्यक्त किया गया। हालांकि, मंगलवार को शिक्षामंत्री भूपेन्द्रसिंह चुडासमा ने राज्य की स्कूलों में वेकेशन नहीं बढ़ाने का सरकार का निर्णय घोषित किया गया। उल्लेखनीय है कि, आगामी १० जून से नये शैक्षणिक सत्र का प्रारंभ हो रहा है। कुछ समय पहले शिक्षामंत्री को गर्मी वेकेशन १७ जून तक बढ़ाने के लिए पेशकश की गई थी, क्योंकि फिलहाल प्रचंड गर्मी है तो दूसरी तरफ तक्षशिला अग्निकांड को लेकर कई स्कूलों में फायर सेफ्टी को लेकर तोड़फोड़ और कार्रवाई की जा रही है तब स्कूलों के शिक्षा कार्य और विद्यार्थियों के कोर्स में कोई बाधा नहीं हो अभिभावक मंडल की तरफ से स्कूलों में वकेशन बढ़ाने की मांग की थी। लेकिन राज्य के शिक्षामंत्री भूपेन्द्रसिंह चुडासमा ने एक बयान में स्पष्ट कर दिया है कि, स्कूलों गर्मी वेकेशन नहीं बढ़ाया जाएगा। लेकिन आगामी १३ से १५ जून के दौरान स्कूल प्रवेशोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। भीषण गर्मी होने की वजह से बच्चे सनस्ट्रोक का शिकार नहीं बने इसके लिए गर्मी वेकेशन बढ़ाया जाए ऐसी मांग अभिभावक मंडल ने उठाई है। दूसरी तरफ वेकेशन बढ़ाने का स्कूल संचालक मंडल द्वारा विरोध व्यक्त किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, आगामी दस दिन तक भीषण गर्मी झेलनी पड़ेगी। गर्मी वेकेशन पूरा होने को एक सप्ताह का समय नहीं बचा है, तब भीषण गर्मी के बीच यदि आगामी दिनों में स्कूल हररोज के अनुसार शुरू होंगे तो बच्चों को गर्मी या लू लगने की भी संभावना रही है।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ऑफसेट एफपी. 149, प्लोट 26 खोडियार नगर, सिद्धीविनायक मंदिर के पास, (भाटेना) हॉ.सो. अंजना सूरत, गुजरात से मुद्रित, एवं 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात से प्रकाशित, **संपादक :- सुरेश मौर्या** फोन नं. (9879141480) **RNI.No. : GUJHIN/2018/75100, E-mail: krantisamay@gmail.com (subject to surat jurisdiction)**